पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी में पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र वितरण एवं 417 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी सौंपी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में डबल इंजन सरकार 'पर हित सरिस धर्म नहिं भाई' के भाव को जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से कार्य कर रही : मुख्यमंत्री

बांग्लादेश से आये हुए लोगों की बस्ती मियांपुर गांव का नाम रविन्द्रनगर किया जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गांव के प्रधान को केन्द्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका

बंगाली विस्थापित सीमा पार कर अपने टूटे हुए सपनों, पीड़ा, बिछड़े हुए स्वजनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर भारत आये, हिन्दुस्तान ने आप सभी को गले लगाया और सम्मान दिया

अब इन्हें कोई विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से इनको अधिकार दिया, उसी की बदौलत भौमिक अधिकार पत्र प्रदान कर रहे, अब यह लोग अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए

अब सभी बंगाली विस्थापितों को सुरक्षित और स्थिर जीवन की एक गारण्टी मिली, बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नीव मिली, बांग्लाभाषी परिवार पूरे आत्मगौरव और सम्मान के साथ अपने वर्तमान और भविष्य के सुनहरे सपने को लेकर पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते

मोहम्मदी तहसील में केतकी का फूल खिलता, जो दुनिया में कहीं नहीं खिलता, सरकार इसको पहचान दिलाने का कार्य करेगी

नये भारत का नया उ0प्र0 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप स्वयं को तैयार कर रहा

लखीमपुर में एक मेडिकल कॉलेज बन चुका, एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा

भारत के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर भौमिक अधिकार प्रदान किये जा रहे, यह केवल भौमिक अधिकार नहीं, बल्कि स्वावलम्बन, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी अधिकार

लखीमपुर खीरी जनपद प्रदेश का भौगोलिक व खेती–किसानी की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, यहां की उर्वरा भूमि में पर्याप्त गन्ना, मेंथा, धान और गेहूं पैदा होता, इसका वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर, जो सबका पेट भरता तथा सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता,

श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर गोला–गोकर्णनाथ शिव मन्दिर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा, प्रदेश सरकार ने इसके लिए धनराशि दी, कॉरिडोर के विकसित हो जाने से पर्यटन व रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी

भारत की पहली पी0एल0ए0 यूनिट जनपद लखीमपुर में स्थापित की जा रही, जो इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी, यहां ऐसा प्लास्टिक बनेगा, जो प्रदूषण नहीं करेगा

दुधवा नेशनल पार्क बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा

'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' के साथ–साथ 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' की भी योजना आगे बढ़ी

हाल की अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के साथ–साथ 'मुख्यमंत्री किसान आपदा सहायता योजना' के माध्यम से किसानों की सहायता की जा सके

जनहानि पर 24 घण्टे में उनको सहायता राशि मिले, पशु हानि पर भी मुआवजा की राशि तत्काल दी जाए, फसल के अग्निकांड की चपेट में आ जाने पर मण्डी समिति तत्काल सम्बन्धित किसानों को मुआवजा दे

अग्निकाण्ड अथवा आंधी–तूफान की चपेट में किसी गरीब का घर आ जाने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उस परिवार को तत्काल एक आवास उपलब्ध कराया जाए

लखनऊ : 11 अप्रैल, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारतीय परम्परा में धर्म की व्याख्या बहुत सहज और सरल है। विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में डबल इंजन सरकार 'पर हित सरिस धर्म नहिं भाई' के भाव को जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। जब बंगाली परिवार विस्थापित होकर यहां आए, तो उनके पास कोई सहारा नहीं था। यह केवल एक विस्थापन की कहानी या अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक साहस, संघर्ष तथा अदम्य जीवटता की एक अमरगाथा है।

मुख्यमंत्री जी आज मियांपुर (मोहम्मदी), लखीमपुर खीरी में पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र वितरण एवं 417 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 213 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक तथा मुख्यमंत्री

आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये। मुख्यमंत्री जी ने संविलियन विद्यालय मियांपुर में बच्चों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभाजन त्रासदी के उपरान्त यहां बसने वाले बंगाली परिवारों को आज भौमिक अधिकार देते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। पाकिस्तान के पाप के कारण इन परिवारों पर अत्याचार हुआ। बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया और उनकी जमीन एवं पैतृक सम्पत्ति पर वहां के कुछ दरिन्दों ने कब्जा कर लिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन परिवारों को उनका अधिकार नहीं दिया। डबल इंजन सरकार की वर्ष 1947 तथा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से आये विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार देने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बांग्लादेश से आये हुए लोगों की बस्ती मियांपुर गांव का नाम रविन्द्रनगर किया जाएगा। अब इस गांव की पहचान भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर होगी। इस रविन्द्र नगर ने पहले ही अपनी एक नई कहानी लिखी है। गांव के संविलियन विद्यालय की तस्वीर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भी टंगी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गांव के प्रधान को केन्द्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

बंगाल की भूमि भारत की आध्यात्मिक–विरासत की भूमि है। यह वर्ष बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। इस वर्ष विस्थापित बंगाली परिवारों को उस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है, जिस भूमि पर वह वर्षों से बसे थे, लेकिन अधिकारों से वंचित थे। दशकों से अधूरे वादों को पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी की ओर से वह स्वयं आये हैं। यह वादा ही नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और मानवीय पक्ष को भी प्रतिबिम्बित करता है, जो प्रधानमंत्री जी के 'सबका साथ, सबका विकास' के उद्घोष में गूंजता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां जिन परिवारों को भौमिक अधिकार दिये गये हैं, उनके पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश में रह रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी के कारण उनको भारत में मालिकाना हक मिल रहा है। न्याय, सम्मान, स्वावलम्बन एवं मानवता की इस लड़ाई को इन लोगों ने संघर्षों के साथ प्रारम्भ किया तथा आज सम्मान के साथ अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नये भारत का नया उत्तर प्रदेश संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता एवं सुशासन की पहचान बन रहा है।

बंगाली विस्थापित सीमा पार कर अपने टूटे हुए सपनों, पीड़ा, बिछड़े हुए स्वजनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर भारत आये थे। उन्होंने अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनकी आजीविका छीनी गई। अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा। इन सबके बावजूद आशा थी कि भारत में ठिकाना और सम्मान मिलेगा। हिन्दुस्तान ने आप सभी को गले लगाया और सम्मान दिया। संघर्ष से सबल बनने की आपकी यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है।

विभाजन की त्रासदी 1947 में इसलिए आयी, क्योंकि हम विभाजित थे। आज भी जो जातियों के बीच विभाजन करने का पाप करता है, वह समाज के सामाजिक ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करता है। वह देश के साथ विश्वासघात करता है तथा आने वाली पीढ़ी के भरोसे के साथ विश्वासघात करता है। पाकिस्तान का बनना और सन् 1947 की भारत विभाजन की त्रासदी या सन् 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान विस्थापित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की त्रासदी को हम सभी ने देखा है। लखीमपुर खीरी में बसे 331 परिवारों को 542 हेक्टेयर भूमि का मालिक बनाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। 331 विस्थापित परिवारों में सदस्यों की संख्या आज बढ़कर 5,000 से अधिक हो गई है। इन लोगों को कभी उनका अधिकार नहीं मिल पाया था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। आने वाला समय जब पूछेगा कि बंगाली बोलने वाले इतनी बड़ी संख्या में कहां से आए हैं। तब यह लोग बताएंगे कि उन्हें जब अपनी भूमि से विस्थापित किया गया, तब लखीमपुर और उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया। परिश्रम को परिणति तक पहुंचते हुए यह लोग आंखों से देख रहे हैं। इनके संघर्ष को पहचान तथा भविष्य को स्थायित्व मिला है। अब इन्हें कोई विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से इनको अधिकार दिया है। आज उसी की बदौलत हम यह भौमिक अधिकार पत्र प्रदान कर रहे हैं। अब यह लोग अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। अब सभी को सुरक्षित और स्थिर जीवन की एक गारण्टी मिल गई है तथा बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नीव मिल गई है। यही प्रधानमंत्री जी की गारण्टी है।

अब कोई इन पर अत्याचार नहीं कर सकता। अब इनको तुष्टिकरण के नाम कोई बहका नहीं सकता। अब कोई इनके मोहल्ले का नाम गुलामी के प्रतीकों के आधार पर नहीं रख सकता तथा कोई इनकी पहचान को समाप्त नहीं कर सकता। उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता तथा भगा नहीं सकता। अब कोई इनको बांग्लादेशी नहीं, बल्कि बांग्लाभाषी बोलेगा, क्योंकि बांग्लाभाषी भी भारत का नागरिक है। यह सभी बांग्लाभाषी परिवार पूरे आत्मगौरव और सम्मान के साथ अपने वर्तमान और भविष्य के सुनहरे सपने को लेकर पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार 'हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार' के विजन तथा प्रत्येक परिवार को सम्मान दिलाने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। नये भारत का नया उत्तर प्रदेश 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप स्वयं को तैयार कर रहा है। आज प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' है। लखीमपुर में एक मेडिकल कॉलेज बन चुका है। यहां एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं और सिखों की संख्या लगभग 65,000 है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इन सभी हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन परिवारों को मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार के द्वारा इतने व्यापक पैमाने पर भौमिक अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। यह केवल भौमिक अधिकार नहीं, बल्कि स्वावलम्बन, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी अधिकार है।

विकास का मतलब केवल सड़क, पुल बनाना नहीं, बल्कि समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है। यह कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है। आज यहां पर प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। जिसको अभी तक नहीं मिला है, उसे भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा। हर घर में शौचालय बना है। हर बस्ती तक बिजली पहुंची है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजना है। प्रदेश सरकार उनको निःशुल्क दो यूनिफार्म, बैग, किताब, जूता–मोजा, स्वेटर उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज यहां की चार विधान सभाओं में 417 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वर्ष 2025 में भी यहां 1,622 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लखीमपुर खीरी जनपद सबको अपने साथ जोड़ता है। यह प्रदेश का भौगोलिक व खेती–किसानी की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। इसका वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर है, जो सबका पेट भरता तथा सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आज यहां सबकुछ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर यहां गोला–गोकर्णनाथ शिव मन्दिर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए धनराशि दे दी है। इस कॉरिडोर के विकसित हो जाने से यहां पर्यटन व रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। भारत की पहली पी0एल0ए0 यूनिट यहां स्थापित की जा रही है, जो इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। यहां ऐसा प्लास्टिक बनेगा, जो प्रदूषण नहीं करेगा। उस प्लास्टिक को

यूज करने के बाद फेंक देने के बाद मिट्टी के संपर्क में आने पर दो–तीन महीने में डिजॉल्व होकर मिट्टी का हिस्सा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जनपद में बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' के साथ–साथ 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' की भी योजना आगे बढ़ी है। यहां की उर्वरा भूमि में पर्याप्त गन्ना, मेंथा, धान और गेहूं पैदा होता है।

अभी हाल ही में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए जिला प्रशासन को शीघ्र सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के साथ–साथ 'मुख्यमंत्री किसान आपदा सहायता योजना' के माध्यम से किसानों की सहायता की जा सके। जनहानि पर 24 घण्टे में उनको सहायता राशि मिल जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजा की राशि तत्काल दी जाए। फसल के अग्निकांड की चपेट में आ जाने पर मण्डी समिति तत्काल सम्बन्धित किसानों को मुआवजा दे। अग्निकाण्ड अथवा आंधी–तूफान की चपेट में किसी गरीब का घर आ जाने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उस परिवार को तत्काल एक आवास उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोहम्मदी तहसील में केतकी का फूल खिलता है, जो दुनिया में कहीं नहीं खिलता। सरकार इसको पहचान दिलाने का कार्य करेगी। अब आपकी पहचान विकास से होगी, जो डबल इंजन सरकार का संकल्प है। इससे आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए डबल इंजन की डबल स्पीड का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि जाति, मत और क्षेत्र में मत बंटें। सबका साथ–सबका विकास के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ जाति, क्षेत्र व भाषा के भेदभाव के बिना प्रत्येक दलित, वंचित और पिछड़े को मिल रहा है।

कार्यक्रम को जनपद के प्रभारी मंत्री तथा आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नितिन अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरुण कुमार सक्सेना, विधान परिषद सदस्य श्री अनूप गुप्ता, विधायक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री सौरभ सिंह 'सोनू', श्री योगेश वर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

————————

PN-CM-Mohammadi, Lakhimpur Kheri Visit-Land Allotment Distribution-11 April, 2026